भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2560
10.08.2026 को उत्तर देने के लिए

तेलंगाना में केंद्रीय अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी

2560. डा. के. लक्ष्मणः

क्या सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) तेलंगाना राज्य में वर्तमान में केंद्रीय क्षेत्र की कितनी अवसंरचना परियोजनाओं की निगरानी की जा रही है;
(ख) आज की तिथि के अनुसार राज्य में ऐसी कितनी परियोजनाएँ लागत वृद्धि अथवा निर्धारित समय-सीमा से अधिक विलंब की स्थिति का सामना कर रही हैं;
(ग) राज्य की इन परियोजनाओं की कुल अनुमोदित लागत और नवीनतम अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी को बेहतर बनाने और परियोजनाओं में होने वाले विलंब को कम करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) तथा संस्कृति मंत्रालय राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह)

(क), (ख) और (ग): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) को 150 करोड़ रुपये और उससे अधिक लागत वाली चल रही केंद्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की स्थिति की निगरानी और ऑनलाइन पोर्टल/वेब निगरानी प्रणाली "परियोजना मूल्यांकन अवसंरचना निगरानी और राष्ट्रीय निर्माण हेतु विश्लेषण (पैमाना)" के माध्यम से करने का अधिदेश दिया गया है। सभी संबंधित मंत्रालय/विभाग/कार्यान्वयन एजेंसियाँ ऐप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस और डेटा एंट्री मोड के माध्यम से पैमाना पोर्टल पर परियोजनाओं की जानकारी नियमित रूप से अपडेट करती हैं।

तद्नुसार, इस मंत्रालय द्वारा सभी चल रही अवसंरचना परियोजनाओं और तेलंगाना राज्य से संबंधित परियोजनाओं का परियोजना-वार विवरण https:/paimana-proj.mospi.gov.in/ReportPage वेबसाइट पर प्रकाशित 'फ्लैश रिपोर्ट' में उपलब्ध है।

(घ): सभी हितधारकों (अवसंरचना संबंधी मंत्रालय/विभाग) को पैमाना पर उपलब्ध डेटा विश्लेषण के आधार पर उनकी परियोजना के कार्यान्वयन और उसमें हुए विलंब के संबंध में नियमित रूप से सूचित किया जा रहा है, ताकि वे अपनी ओर से परियोजना कार्यान्वयन के प्रबंधन में आवश्यक हस्तक्षेप कर सकें। इसके अतिरिक्त, मासिक समीक्षा बैठकों और अन्य संचार माध्यमों से हितधारकों के साथ नियमित समन्वय साक्ष्य-आधारित निगरानी में योगदान देता है। इसके अतिरिक्त, अनुकूलित डैशबोर्ड तक पहुंच प्रदान करने वाले लॉगिन क्रेडेंशियल पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ साझा किए जा चुके हैं, जिससे उन्हें परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए पोर्टल तक सीधी पहुंच प्राप्त हो जाती है।

*****